गहरे जल संकट की ओर बढ़ रहा ईएसआई मेडिकल कॉलेज

कैम्पस में फैला रहता है बाहर से आया गंदा पानी

फ़रीदाबाद (म.मो.) 30 एकड़ के भूखंड पर बना ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल बड़ी तेज़ी से पेय जल संकट की ओर अग्रसर है। कुल मिला कर 700 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में प्रति दिन 3500 से 4000 तक मरीज़ ओपीडी में आते हैं। 500 छात्र यहां के हॉस्टल में रह कर पढ़ाई करते हैं। डॉक्टरों, मेडिकल व अन्य स्टाफ़ की संख्या भी 500 से कम नहीं है। इनमें से सैंकड़ों स्टाफ़ परिसर में ही बने आवासों में रहते हैं।

इन सब लोगों को जलापूर्ति के लिये परिसर में 13 ट्यूबवेल लगे हैं जिनमें से अधिकांश सूख चुके हैं। इसके चलते आज भी यहां पर यदा-कदा जलापूर्ति की समस्या बनी रहती है। लेकिन जिस तरह से भूजल स्तर गिरता जा रहा है, आने वाले समय में बाकी ट्यूबवेल भी बहुत समय तक पानी नहीं दे पायेंगे। भविष्य में आने वाली इस समस्या को भांपते हुए मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का निर्माण करते समय इसी बात को ध्यान में रखते हुए पानी की बर्बादी को रोकने के उद्देश्य से सीवेज को ट्रीट (शोधन) करके उस पानी को शौचालयों में इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। इसके लिये बाकायदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट व उससे शोधित पानी को शौचालयों तक पहुंचाने के लिये पाइप लाइन भी बिछाई गई थी। इसी पानी से परिसर में पेड़-पौधों आदि की सिंचाई भी सुनिश्चत की गई थी। लेकिन आज तक एक दिन भी शोधित पानी शौचालयों तक नहीं पहुंच पाया। प्रारम्भिक एक-दो साल तो एसटीपी ने जल शोधन का काम किया लेकिन अब यह प्लांट पूरी तरह से ठप्प है। सारा सीवेज बिना शोधन के अनाधिकृत रूप से परिसर के बाहर इधर-उधर निकाला जा रहा है क्योंकि प्रारम्भिक योजना के अनुसार सीवेज को बाहर निकालने के लिये नगर निगम से कोई कनेक्शन लिया ही नहीं गया था और उसकी जरूरत भी नहीं थी। कई बार तो यह सीवेज उफ़न कर परिसर में ही फैलता रहता है।

वर्षा जल को संचित करने की भी कोई व्यवस्था यहां नहीं बनाई गई है। यदि इस तरह की कोई व्यवस्था बनाई गई होती तो आज यह समस्या उत्पन्न न हुई होती।

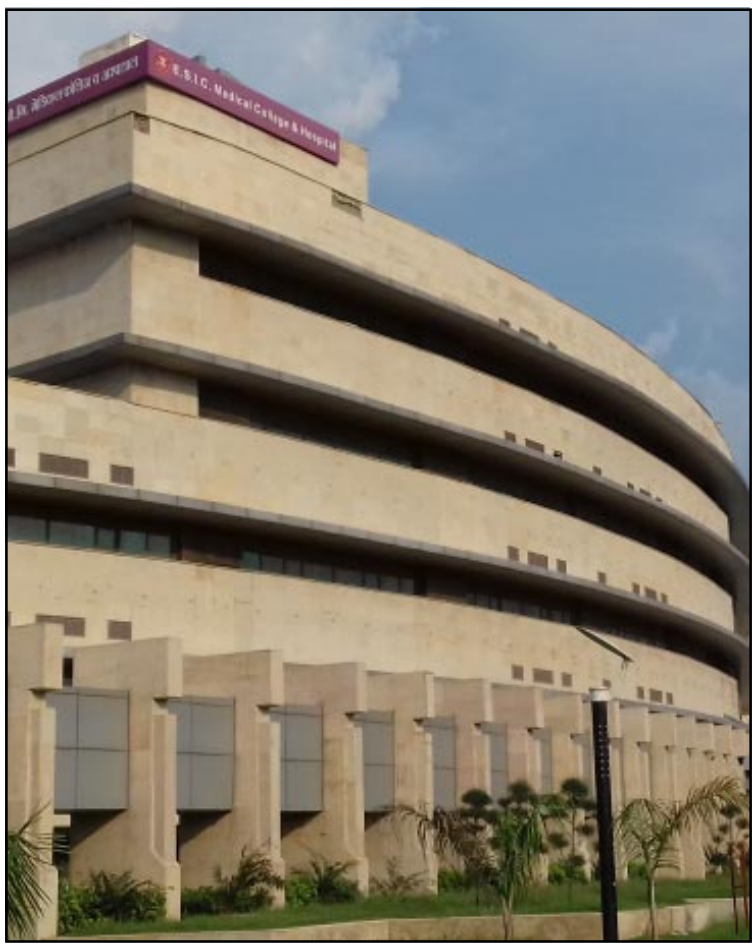

इमारतों की छत पर बरसने वाले पानी को सीधे ही स्टोर करके पीने के काम में लिया जा सकता था जिसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसके लिये केवल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूर लगाये गये हैं जो काम नहीं करते। राहुल कॉलोनी की ओर लगने वाली परिसर की दीवार के साथ जो हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे हैं, उन्हें राहुल कॉलोनी की ओर से आने वाले गंदे नाले के पानी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। सुनने में जरूर थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि उस गंदे नाले का पानी दीवार में से लीक होकर भारी मात्रा में कॉलेज परिसर में भरा रहता है और वहीं पर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगे हैं।

संदर्भवश बता दें कि यह गंदा नाला नगर निगम द्वारा संचालित है। जो नगर निगम एक बूंद पेय जल इस कॉलेज को दे नहीं सकता, वह पर्याप्त मात्रा में गंदा पानी कॉलेज परिसर में भरता रहता है। यह भी एक आश्चर्यजनक सत्य है कि नगर निगम मज़दूरों के इस कॉलेज अस्पताल से कंपलीशन के नाम पर पांच करोड़ रुपये तो वसूल सकता है लेकिन पानी और सीवरेज की सुविधा नहीं दे सकता। दूसरी मजेदार बात यह है कि पड़ोस में ही बने बीके अस्पताल व अन्य अनेकों सरकारी बिल्डिंगों का न तो कोई नक्शा पास हुआ है और न ही कोई कम्पलीशन हुआ है। लेकिन, इसके बावजूद कोविड संकट के समय शासन-प्रशासन ने इस अस्पताल को मज़दूरों से छीन कर अपने कब्जे में लेकर पूरी दादागिरी चलायी थी।

परिसर की देख-भाल यानी कि इंजीनियरिंग से सम्बन्धित बिजली, पानी, सीवर व पेड़ पौधों की देख भाल तक का दायित्व, मेडिकल कॉलेज के डीन की अपेक्षा सेक्टर 16 में बैठे क्षेत्रीय निदेशक के पास हुआ करता था। जाहिर है कि दूर बैठे निदेशक महोदय को मेडिकल कॉलेज की दिन प्रतिदिन की समस्याओं से क्या लेना-देना? जिस डीन के सिर पर आये दिन ये समस्यायें नाचती रहती हैं, उनके पास इन्हें हल करने का कोई अधिकार नहीं था। करीब सात-आठ साल के बाद यह व्यवहारिक समस्या नई दिल्ली स्थित मुख्यालय की समझ में आई तो उसने क्षेत्रीय निदेशक को बीच से हटा कर यह सारा दायित्य एवं अधिकार डीन को सौंप दिये हैं। अब कुछ सुधार की अपेक्षा की जा सकती है।

ईएसआई मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब लगाने की तैयारी

फ़रीदाबाद (म.मो.) एनएच तीन स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अपने बीमा धारकों को बेहतरीन सेवायें देने के प्रयास में लगातार जुटा है। अभी तक जिन हृदय रोगियों को स्थानीय एसियन, फोर्टिस व मैट्रो जैसे व्यापारिक अस्पतालों के धक्के खाने पड़ते थे, उनमें से अधिकांश का सम्पूर्ण इलाज करने के लिये यहां पर कैथ लैब लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। करीब 10 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली यह लैब दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह या जनवरी 2022 के पहले सप्ताह में चालू हो जायेगी। ऑर्डर पर बनने वाली इस मशीन के लिये जर्मनी की सीमेंस कम्पनी को ऑर्डर के साथ एडवांस पेमेंट कर दी गई है।

विदित है कि अभी तक इस मशीन के अभाव में मरीजों को उक्त व्यापारिक अस्पतालों को रेफ़र किया जाता था जिसके लिये ईएसआई कॉर्पोरेशन को उन्हें भारी-भरकम पेमेंट करनी पड़ती है। इस पेमेंट करने के बावजूद इन व्यापारिक अस्पतालों का व्यवहार मरीज़ों के साथ बहुत ही बुरा होता है। वहां इन मरीज़ों को दोयम दर्जे का समझा जाता है क्योंकि ईएसआई का जो रेट कॉन्ट्रेक्ट होता है, उससे कहीं ज्यादा वसूली ये अस्पताल वाले अन्य मरीज़ों से कर लेते हैं। इसी के चलते ईएसआई से आने वाले मरीजों को आसानी से ये अस्पताल भर्ती भी नहीं करते हैं; इन्हें केवल तभी भर्ती किया जाता है जब अधिकांश बेड खाली हों। इतना ही नहीं इन मरीजों को डरा-धमका कर कई तरह से अतिरिक्त वसूली भी इन से कर ली जाती है।

हृदय रोग के बाद, 2022 तक कैंसर इलाज से सम्बन्धित लगभग सभी मशीनें व उपकरण आदि भी लगाने की तैयारी चल रही है। फ़िलहाल यहां पर एंकॉलॉजिस्ट द्वारा कैंसर मरीज़ों को दवाई देने का कार्यक्रम तो चल रहा है लेकिन पैट स्कैनिंग व रैडियो थैरपी का इंतजाम यहां न होने की वजह से भारी मात्रा में मरीजों को रैफ़र किया जाता है। समझा जाता है कि अगले एक वर्ष में उक्त दोनों मशीनों का संचालन भी यहां शुरू हो जायेगा। जाहिर है कि इससे बीमा धारक मरीज़ों को इलाज के लिये अत्यधिक सुविधा हो जायेगी।

राजकीय नेहरू कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं की लीपा-पोती करने आई जांच टीम

फ़रीदाबाद (म.मो.) करीब एक साल पूर्व मज़दूर मोर्चा ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल ओपी रावत द्वारा की गई कुछ वित्तीय अनियमितताओं अथवा घोटालों को लेकर समाचार प्रकाशित किया था। इसके बावजूद सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उसके कुछ दिन पश्चात मौजूदा प्रिंसिपल ने अपने विभाग को उन घोटालों के बारे में बाकायदा पत्र लिख कर सूचित किया। अब क्योंकि विभाग के पास लिखित रूप में और सीधे तौर पर सूचना आ गई थी तो उस पर बहुत समय तक कुंडली मार कर बैठे रहना सम्भव नहीं था। फ़िर भी विभाग ने जांच का नाटक करने में छः माह से अधिक का समय लगा दिया।

विदित है कि ओपी रावत नियमित प्रिंसिपल नहीं थे। उच्च शिक्षा विभाग में जान-बूझ कर प्रिंसिपलों की कमी बना कर रखी जाती है। किसी कॉलेज में प्रिंसिपल न होने की सूरत में वरिष्ठतम प्रोफेसर को प्रिंसिपल का चार्ज दे दिया जाता है। इस कॉलेज में भी यही प्रक्रिया अपनाने का प्रयास किया गया था। लेकिन तीन वरिष्ठतम प्रोफेसरों द्वारा प्रिंसिपल का चार्ज लेने से मना कर देने के बाद ओपी रावत के भागों प्रिंसिपल पद का छींका टूटा। पदासीन होते ही रावत महोदय ने कई तरह के गुल खिलाने शुरू कर दिये थे। इन्हीं में से कुछ मामला लाखों रुपये के घोटालों से सम्बन्धित थे।

विदित है कि कोई भी अधिकारी इस तरह के घोटाले केवल तभी करता है जब उसका विश्वास होता है कि वह जो मर्जी कर ले उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। उसे यह भरोसा इसलिये होता है कि उसका बिगाड़ सकने वाले सक्षम अधिकारी भी घोटालों में से अपना हिस्सा ले चुके होते हैं। फ़िर भी यदि कोई समस्या आ ही जाये तो उससे निपटने के लिये राजनेता तो हाजिर रहते ही हैं।

इसी के चलते रावत महोदय खुल कर खेलते रहे और अब कहीं जाकर मुख्यालय चंडीगढ से चार सदस्यीय टीम, जिसे हाई पॉवर कमेटी बताया गया है, बीते सप्ताह यहां पहुंची। इस कमेटी ने दो दिन तक कॉलेज में सम्बन्धित कागज-पत्तर खंगाले। अब देखने वाली बात यह है कि इस सारी कवायद का परिणाम क्या निकलता है?

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06